

रजिस्टर्ड नं० ल०-३३/एस० एम १४/९१.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९९१/१५ भाद्रपद, १९१३

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक (नियुक्ति-II) विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-२, २५ अप्रैल, १९८९

संख्या पी० ई० आर० (ए० पी०-II) ए(३)-११/८२-III—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण भूतपूर्व सैनिक नियम, १९८५ में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (हिमाचल प्रदेश तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) (द्वितीय संशोधन) भूतपूर्व सैनिक नियम, १९८९ है।

(ii) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 3 (1) और (2) का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश (तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) भूतपूर्व सैनिक नियम, 1985 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (i) और (ii) के विद्यमान उपबन्धों के लिए निम्नलिखित उप-नियम (1) और (2) प्रति-स्थापित किये जायेंगे :—

“3(1) हिमाचल प्रदेश तकनीकी सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से 15 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए आरक्षित रखी जाएंगी । वर्ग-3 और 4 के पदों में इस 15 प्रतिशत आरक्षण के अन्तर्गत युद्ध में मारे गये या असैनिक नियोजन के लिए अयोग्य रक्षा कार्मिक के एक आश्रित की नियुक्ति भी है । ऐसे आश्रितों की नियुक्ति के लिए, पद/पदों के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी किन्तु वे नियम 5 (1) के अन्तर्गत किसी अन्य प्रसुविधा/रियायत, जैसे कि वेतन का नियतन और ज्येष्ठता के हकदार नहीं होंगे । परन्तु जो भी रिक्तियां, उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों, जिन्होंने नवम्बर, 1962 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् सेवा में प्रवेश या कमीशन प्राप्त किया था, और यथा उक्त उपबन्धित आश्रितों के उपलब्ध न होने के कारण रिक्तियां भरी नहीं जाती हैं तो ऐसी रिक्तियां उन उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों में से भरी जाएंगी जिन्होंने नवम्बर, 1962 के प्रथम दिन से पूर्व सेवा में प्रवेश या कमीशन प्राप्त किया था । तथापि, इन नियमों के नियम 5 (1) में यथा-उपबन्धित ज्येष्ठता या वेतन नियत करने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित सैनिक सेवा का गणना में लिया जाना, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) जहां किसी वर्ष में उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों तथा रक्षा सेवा कार्मिक या युद्ध में मारे गये हैं या असैनिक नियोजन के लिए अयोग्य हो गये हैं, के आश्रितों के न होने के कारण उनके लिए आरक्षित रिक्तियों, उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों या यथा उक्त दशित आश्रितों के न होने के कारण खाली रह जाती हैं तो ऐसी रिक्तियां, अनारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तत्समय प्रवृत्त भर्ती नियमों के अनुसार किसी अन्य सूत्र से अस्थायी रूप में भरी जाएंगी । ऐसी रिक्तियों की संख्या अगले वर्ष में गणना में ली जाएगी, परन्तु ऐसी रिक्तियां चार वर्ष से अधिक के लिए संगठित नहीं की जाएंगी :

परन्तु यह और कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित पुत्र, पुत्रियां और पत्नियों को भी जो विभिन्न पदों के लिए विहित शिक्षा आयु आदि की शर्तें पूरी करती हों, भूतपूर्व सैनिकों [नियम 3(1) में यथा-वर्णित एक आश्रित को सम्मिलित करते हुए] के लिए आरक्षित पदों के लिए उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों जिसके अन्तर्गत उक्त नियम 3(1) में दशित एक आश्रित भी है के उपलब्ध न होने पर, चार वर्ष के पश्चात् गुणागुण के आधार पर विचार में लिया जायेगा और यदि भूतपूर्व सैनिक का कोई पुत्र/पुत्री/पत्नी पांचवें वर्ष में उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो रिक्तियां व्ययगत् हो जाएंगी । ऐसा अधिकार केवल एक आश्रित प्रतिपाल्य/पत्नी को ही प्राप्त होगा । इन नियमों के अधीन आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपाल्य/पत्नियों का चयन किए जाने पर वे इन नियमों के अधीन भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली किसी भी अन्य प्रसुविधा के हकदार नहीं होंगी :

परन्तु यह और भी कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी सेवाओं में अग्रनयन सहित, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गये या असैनिक नियोजन के लिए अयोग्य हुए रक्षा सेवा कार्मिक के आश्रितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अन्य प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या, एक वशिष्ट अवसर पर भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा ।”

[Authoritative English text of this Department notification No. Per. (AP-II)A(3)-11/82-III, dated 25-4-1989 as required under clause (3) of Article 343 of the Constitution of India is hereby published].

Shimla-2, the 25th April, 1989

No. Per. (AP-II)A(3)-11/82-III.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, hereby makes the following rules further to amend the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) (Second Amendment) Rules, 1989.

(2) These shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment of Rule 3 (1) and (2).*— For the existing provisions of sub-rules (1) and (2) of rule 3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 (here-in-after called the said rules), the following sub-rules (1) and (2) shall be substituted :—

“3(1) Fifteen per cent of the vacancies to be filled by direct recruitment in Himachal Pradesh Technical Services shall be reserved for being filled in by recruitment of Ex-servicemen. This 15% reservation in Class III and IV posts will also include appointments of one dependent of those Defence Services Personnel who were killed in action or disabled in action and rendered unfit for civil employment. Such dependents shall have to fulfil the requirements of the Recruitment and Promotion Rules of the post (s) to which they will be appointed, but they shall not be entitled for any other benefits/concessions such as fixation of pay and seniority under rule 5(1) :

Provided that whatever vacancies are left over due to non-availability of suitable ex-servicemen who joined service or were commissioned on or after the 1st day of November, 1962 and the dependents as provided above, will be filled by suitable ex-servicemen who joined service or were commissioned before 1st day of November, 1962. The concessions such as relaxation in age as prescribed in these rules shall also be admissible to such Ex-servicemen. However, the benefit of counting the period of approved military service for the purpose of fixation of seniority and pay as provided in rule 5(1) of these rules, shall not be admissible to such Ex-servicemen.

(2) Where in any year, vacancies reserved for the ex-servicemen and the dependents of the Defence Services Personnel who were killed in action or disabled in action and rendered unfit for civil employment remain unfilled for want of suitable ex-servicemen or dependents as stated above such vacancies may be filled up temporarily from any other source in accordance with the recruitment rules for the time being in force, for filling up vacancies which are not reserved. The number of such vacancies shall be carried forward to the next succeeding years:

Provided that no such vacancies shall be carried forward for more than four year :

Provided further that dependent sons and daughters and wives of ex-servicemen who fulfil the condition of education, age etc. prescribed for various posts shall also be

considered on merit for the posts reserved for ex-servicemen [including one dependent as in rule 3(1) above] to the extent of non-availability of suitable ex-servicemen [including one dependent as in rule 3(1) above] after four years and if no suitable son/daughter/wife of ex-servicemen is available in the fifth year, the vacancies shall lapse. This entitlement would be available to one dependent, ward/wife only. In the event of selection of the wards/wives of ex-servicemen against the reserved vacancies under these rules, they will not be entitled to any other benefits which are available to the ex-servicemen under these rules :

Provided further that the total number of vacancies reserved for ex-servicemen and the dependents of the Defence Services Personnel killed or disabled in action and rendered unfit for civil employment, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and other categories, along with carry forward reservation in Himachal Pradesh Technical Services shall not exceed 50% (fifty per cent) of the total number of vacancies to be filled up on a particular occasion".

शिमला 2, 25 अप्रैल, 1989

संख्या पी० ई० आर० (ए पी-II)ए(3)-11/82-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, डिमोबिलाइज्ड आर्म्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेंकेंसोज इन हिमाचल स्टेट नान-टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 में प्रौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) (Tenth Amendment) Rules, 1989.

(2) These shall come into force with immediate effect.

2. *Amendment of Rule 3 (1), (2), (3) and (4).*—For the existing provisions of sub-rules (1), (2), 3 and (4) of rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 (here in after called the said rules), the following sub-rules (1) (2), (3) and (4) of rule 3 shall be substituted :—

3 (1) Fifteen per cent of vacancies in respect of all posts viz. Class I, II, III and IV to be filled up through direct recruitment shall be reserved for being filled up by the Released Indian Armed Forces Personnel of ex-servicemen who joined service or were commissioned on or after the 1st day of November, 1962 and are released any time thereafter. This 15% reservation in Class III & IV posts will also include appointments of one dependent each of the family of those Defence Services Personnel who were killed in action or were disabled in action and rendered unfit for civil employment. Such dependents shall have to fulfil the requirements of the Recruitment and Promotion Rules of the post (s) to which they will be appointed, but they shall not be entitled for other benefits/concessions such as fixation of pay and seniority under rule 5 (1) :—

Provided that whatever vacancies are left over due to non-availability of suitable ex-servicemen who joined service or were commissioned on or after 1st day of November, 1962, and the dependents as provided above will be filled by suitable ex-servicemen who joined service or were commissioned before 1st day of November, 1962. The concession such as relaxation in age as provided in these

rules, shall also be admissible to such ex-servicemen. However, the benefit of counting the period of approved military service for the purpose of fixation of seniority and pay as provided in Rule 5 (1) of these rules, shall not be admissible to such ex-servicemen.

- (2) Where in any year any vacancies reserved for the Released Indian Armed Forces Personnel or ex-servicemen who joined service or were commissioned on or after the 1st day of November, 1962 and the dependents of those defence service personnel who were killed in action or disabled in action and rendered unfit for civil employment remain unfilled for want of suitable Released Armed Forces Personnel or dependents as stated above, such vacancies may be filled up temporarily from any other source in accordance with the recruitment rules for the time being in force for filling up vacancies which are not reserved.
- (3) Where in any year any vacancies reserved for the Released Armed Forces Personnel who joined service or were commissioned on or after the 1st day of November, 1962 and the dependents of those Defence Services Personnel who were killed in action or disabled in action and rendered unfit for civil employment have been filled up temporarily in accordance with the provision of sub-rule (2) above the number of vacancies so filled up shall be carried forward to the next succeeding year provided that no such vacancies shall be carried forward for more than four years.
- (4) Notwithstanding anything contained in these rules the total number of vacancies reserved for the Released Armed Forces Personnel who joined service or were commissioned on or after the 1st day of November, 1962 and the dependents of those Defence Services Personnel who were killed in action or disabled in action and rendered unfit for civil employment, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, in any service, shall not exceed in any year 50% of the total number of vacancies to be filled up in that service in that year.

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित,
सचिव ।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 अगस्त, 1991

संख्या गृह (क)-एफ (13)-10/88.--यतः केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र के प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्या 1) के अधीन भूमि अर्जन का कार्य राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का 0 आ 0 782 (अ) दिनांक 25-10-1985 द्वारा सुपुर्द किए गए हैं ;

2. और यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपात्र को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः गांव फाटी बरुआ, कोठी मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा सैन्य के प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतः एवं एतद्वारा यह घोषित

किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना अपेक्षित है ।

3. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु जारी की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (उप-मण्डल अधिकारी) कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

4. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता (उप-मण्डल अधिकारी) कुल्लू, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

5. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (उप-मण्डल अधिकारी) कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : कुल्लू

तहसील : कुल्लू

ग्राम	खसरा संख्या	बीघे	रकबा बिस्वे	बिस्वांसी
1	2	3	4	5
फाटी बरुआ	4834	1	10	0
योग ..		1	10	0

आदेश द्वारा,

अमर नाथ विद्यार्थी,
वित्तायुक्त ।